of the increase in the operational cost of auto-rickshaws.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

1311. श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी में गोलमाल की कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के गोलमाल की भी कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार ने कम्पनी को दिये गये पिछले ऋण की अब तक कुल कितनी रकम वसूल की है तथा कम्पनी ने अभी कितनी रकम और देनी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जयन्ती शिपिंग कंपनी के कामकाज के सम्बन्ध में सरकार को आरोप और शिकायतें मिली हैं, जो अधिकतर गुमनाम हैं ।

(ख) और (ग). चूंकि इन आरोपों की अभी जांच की जा रही है इस लिये लगाये गये आरोपों या शिकायतों के ब्योरों को इस समय बतलाना पूरी तौर से जनहित में न होगा ।

(घ) 11 जहाजों की प्राप्ति के लिये, जिस में से सब मिल चुके हैं, जयन्ती शिपिंग कम्पनी को शिपिंग डिवलपमेंट फंड कमेटी ने 20.25 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था । कमेटी ने अभी तक वास्तव में 5.91 करोड़ रुपये ही दिये हैं और शेष राशि किश्त की अवधि आने पर शिपयार्ड को दी जायेगी । कम्पनी द्वारा मूलधन की पहली पुनर्अदायगी 21 जनवरी, 1966 को पड़ी थी और कुल राशि अर्थात् 12.08 लाख रुपये ठीक तारीख को दे दिये गये थे । इस के अलावा कम्पनी ने अभी एक जहज के बारे में 1.53 लाख रुपये का तदर्थ भुगतान भी किया है । इस प्रकार कम्पनी को 5.77 करोड़ रुपये देना शेष रह जाता है जिस की पुनर्अदायगी कई वर्षों की अवधि में होनी है । उपरोक्त मूलधन की पुनर्अदायगी के अलावा कम्पनी ने सूद की छः किश्तें भी अदा कर दी हैं जो अभी तक देनी थी और जो मिल कर 20.50 लाख रुपये होती थी ।

Panchayat Employees in Kerala

1312. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the house rent allowance allowed to the Government employees is given to Panchayat employees in Kerala also; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). The necessary information has been called for from the Government of Kerala and would be placed on the Table of the House as soon as it is available.

Panchayat Employees in Kerala

1313. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the Kerala Pay Commission's recommendations have been extended to the Panchayat employees in Kerala; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). The necessary information has